

उपभोक्ता की दुनिया

श्रावस्ती से प्रकाशित

वर्ष : 21 अंक : 21	श्रावस्ती, शुक्रवार 27 जून 2025	पृष्ठ : 4	मूल्य : 1 रुपया
--	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------

भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में रचा इतिहास

नई दिल्ली (जएन्सी)। फ्लोरिडा में नासा के कॅनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के अट्हाईस घंटे बाद ग्रुप केंप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया। वैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए, क्योंकि गुरुवार को Axiom-4 (Ax-4) मिशन सफलतापूर्वक ऑर्बिटिंग प्रयोगशाला से जुड़ गया। यह मील का पथर भारत के लिए मानव अंतरिक्ष यान में विजयी वापसी का प्रतीक है, जो 1984 में राकेश शर्मा के अग्रणी मिशन के 41 साल बाद आया है। डॉकिंग से पहले, ड्रैगन अंतरिक्ष यान को आईएसएस के साथ अपनी कक्षा को सावधानीपूर्वक सिंक्रनाइज करना था, जिससे स्थिति और गति दोनों का मिलान हो सके। इस जटिल प्रक्रिया को रेंडेजवस के रूप में जाना जाता है, इसके बाद कैप्सूल को स्टेशन के साथ संरेखित करने और कनेक्ट करने के लिए अत्यधिक सटीक युद्धाभ्यास का क्रम होता है। सबसे पहले, एक र्शोपिट कैंचरश की पुष्टि की गई, जो एक लचीले प्रारंभिक संपर्क का संकेत देता है जिसने अंतरिक्ष यान की गतिज ऊर्जा को सुरक्षित रूप से अवशोषित किया।

अमरनाथ यात्रा पंजीकरण मेंआई गिरावट

जम्मू–कश्मीर (जएन्सी)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पंजीकरण में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। सिन्हा ने राजभवन में घाटदवाताओं से कहा कि 22 अप्रैल की घटना से पहले तीर्थयात्रियों का पंजीकरण अच्छी गति से चल रहा था, लेकिन उसके बाद पंजीकरण में कमी आई। पिछले साल की तुलना में पंजीकरण में 10.19 प्रतिशत की गिरावट आई है। उपराज्यपाल ने कहा कि पहलगाम क्षेत्र के बैसरन में हुए हमले से पहले करीब 2.36 लाख तीर्थयात्रियों ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया था। हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। उन्होंने कहा, ञ्जम्मू-कश्मीर प्रशासन और सुखा बलों द्वारा उठाए गए कदमों के कारण तीर्थयात्रियों में विश्वास लौट रहा है।

बिक्रम मजीठिया 7 दिन की रिमांड पर

पंजाब (एजेंन्सी)। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली जिला अदालत ने सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुरुवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विजिलेंस ब्यूरो ने अदालत में पेश किया। मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद से ही अकाली दल के कार्यकर्ता विरोध ी प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए अदालत परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

मजीठिया की 7 दिन की पुलिस हिरासत पर पंजाब आप अ्ध यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि अदालत ने भी माना है कि आगे की जांच की जरूरत है। पंजाब सरकार और विजिलेंस विभाग ने पूरे तथ्यों के साथ मामले को अदालत में उठाया। नशे की वजह से अपने बच्चों को खोने वालों को न्याय मिले।

राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर का वार

बिहार (एजेन्सी)। बिहार चुनाव के लेकर सियासत तेज है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी जोरों-शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। प्रशांत किशोर भी लगातार अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं, एएनआई से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गंधी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी ने बिहार के किसी गांव में एक रात भी बिताई है? वो दिल्ली में बैठकर बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं और फिर यहां आकर हमें उपदेश देते हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि सीएम बनने के बाद खेत रेंखी ने कहा था कि मजदूर करना बिहारियों के जीवन प में है.. वो कहते हैं कि बिहारी मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं और फिर बिहार में आकर उन्हें उपदेश देते हैं?

सीईएल में विधि-विधान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ग्रीन डाटा सेंटर के लिए भूमि पूजन, रखी आधारशिला



गाजियाबाद (एजेंन्सी)। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) के 51वें स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीईएल में बनने वाले ग्रीन डाटा सेंटर के लिए विधि-विधान से पूजा कर भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में डाटा सेंटर की आध

ारशिला रखी। इसके बाद सीईएल के अध्यक्ष चेतन प्रकाश जैन ने डाटा सेंटर की मॉडल को दिखाते हुए उसकी विशेषताओं और बारीकियों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। कार्यक्रम स्थल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने सीईएल परिसर में अशोक के पौधे का रोपण किया और फिर सीईएल में लगी उपकरण प्रदर्शनी

को भी जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा व भाजपा के अन्य नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अत्याधुनिक डाटा स्टोरेज सेंटर (डाटा सेंटर) के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, ष्रधानमंत्री मोदी ने सभी भारतीयों को

आदित्यनाथ ने कहा कि 8 वर्ष पहले जहां लोग यूपी में निवेश नहीं करना चाहते थे वर्तमान में हर कोई यहां निवेश करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उद्यमियों ने यूपी में 50 लाख करोड़ का निवेश किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज औद्योगिक क्षेत्र साइट चार में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने वह डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हवन किया। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह व उप्र के मंत्री सुनील कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। इसके बाद वह इंदिरापुरम स्थित कैलास मानसरोवर भवन पहुंचे। यहां वह अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विमान सुबह करीब हो, विकसित भारत हो और विकसित भारत का रास्ता इस प्रकार के संस्थानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री योगी

लाइट और साइट चार होते हुए सीईएल पहुंचे। यहां करीब दो घंटे रहने के बाद वह इंदिरापुरम कैलास मानसरोव भवन के लिए रवाना हुए। यहां से वह वसुंरा होते हुए सीआइएसएफ रोड से कैलास भवन जायेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते गाजियाबाद में रूट डायवर्जन प्लान भी किया गया। जिस मार्ग से मुख्यमंत्री निकलेंगे वहां के संपर्क मार्गों पर यातायात कुछ देर पहले से रोक़ा गया और उनके काफिले के निकले के बाद यातायात दोबारा शुरू कर दिया। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) के 51वें स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीईएल में बनने वाले ग्रीन डाटा सेंटर के लिए विधि-विधान से पूजा कर भूमि पूजन किया। इसके बाद सीईएल के अध्यक्ष चेतन प्रकाश जैन ने डाटा सेंटर की मॉडल को दिखाते हुए उसकी विशेषताओं और बारीकियों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी।

भारत ने आतंकवाद पर फिर दिखाया कड़ा रुख, राजनाथ ने एससीओ के बयान पर हस्ताक्षर से किया इनकार

निपटने के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद से निपटने के मामले में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए एससीओ सदस्य देशों को एकजुटता के साथ इस खतरे की निंदा करनी चाहिए। भारत और चीन के अलावा एससीओ में पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान का परोक्ष उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सीमापार आतंकवाद की नीतिगत साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकवाद से बचाव और सीमा पार से होने वाले हमलों को रोकने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। उन्होंने कहा, पहलगाम

आतंकी हमले के दौरान, पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान के आ्ार पर गोली मार दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले का तरीका भारत में लश्कर-ए-तैयबा के पिछले आतंकवादी हमलों के जैसा था। भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति उसके कार्यों से प्रदर्शित होती है। उन्होंने कहा, इस नीति में आतंकवाद से खुद का बचाव करने का हमारा अधिकार भी शामिल है। हमने दिखा दिया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं और हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। सिंह ने कहा कि एससीओ सदस्यों को आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए। उन्होंने इस खतरे से



सभी रूपों में लड़ने के भारत के संकल्प की पुष्टि की। रक्षा मंत्री ने युवाओं में कहरपंथ को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने का भी आह्वान किया। सिंह ने कहा कि दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर हमलों से लेकर हाइब्रिड युद्ध तक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये खतरे सभी देशों

के सामने हैं और इनसे निपटने के लिए पारदर्शिता, आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित एकीकृत प्रयासों की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत, अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा व स्थिरता से संबंधित अपनी नीति पर अडिग रहा है। रक्षा मंत्री एससीओ रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन से भाग लेने के लिए बुधवार को चीन के बंदरगाह शहर किंगदाओ पहुंचे थे।

अमित शाह बोले- भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा है



नई दिल्ली (एजेन्सी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भाषाएँ सिर्फ संचार का मा्धयम नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाषाओं को जीवित रखना और समृद्ध करना जरूरी है। उन्होंने कहा, जहाँ तक देश का सवाल है, भाषा सिर्फ संचार का माध्यम नहीं हैय यह राष्ट्र की आत्मा है। भाषाओं को जीवित रखना

और उन्हें समृद्ध करना महत्वपूर्ण है। हमें आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं और खासकर राजभाषा के लिए ये सभी प्रयास करने चाहिए। दिल्ली में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में बोलते हुए, अमित शाह ने कहा कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की दोस्त है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी और भारतीय भाषाएँ मिलकर राष्ट्र के

केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए, इस दौरान अमित शाह ने कहा कि किसी भाषा का विरोध नहीं है

आत्म-सम्मान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं दिल से मानता हूँ कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की दुश्मन नहीं हो सकती।

हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की दोस्त है, और हिंदी और भारतीय भाषाएँ मिलकर हमारे आत्म-सम्मान के कार्यक्रम को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। किसी भी भाषा का विरोध नहीं हैय किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन जोर अपनी भाषा को गौरवान्वित करने पर होना चाहिए, अपनी भाषा बोलने पर जोर होना चाहिए, और अपनी भाषा में सोचने पर जोर होना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि पूरे देश को

गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने की जरूरत है। उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, “हमें गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाना चाहिए। और जब तक कोई व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं करता, अपनी भाषा में खुद को व्यक्त नहीं करता, हम गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते।” मंत्री ने छात्रों को कई भारतीय भाषाओं में प्रतियोगी परीक्षाएँ देने में सक्षम बनाने के लिए सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि किसी भाषा का विरोध नहीं है, किसी विदेशी

भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन आग्रह अपनी भाषा का महिामांड़न करने का होना चाहिए, आग्रह अपनी भाषा बोलने का होना चाहिए, आग्रह अपनी भाषा में सोचने का होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना चाहिए। और जब तक व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेगा, अपनी भाषा में अपनी बात नहीं कहेगा, तब तक हम गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। अमित शाह ने आगे कहा कि जहां तक देश का सवाल है, भाषा सिर्फ संवाद का मा्धयम नहीं है, यह राष्ट्र की आत्मा है। भाषाओं को जीवित रखना और उन्हें समृद्ध बनाना जरूरी है।



अरविंद केजरीवाल के अहंकार को दर्शाती हैं। विजिलेंस ने मेरे घर में जबरदस्ती प्रवेश किया और प्रेस को भी अंदर नहीं आने दिया। इतना ही नहीं, वकीलों के साथ भी धक्का-मुक्की

की। आम आदमी पार्टी की सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है। भगवंत मान की धमकियां मुझे चुप नहीं करा सकतीं। मैं हमेशा पंजाब और पंजाबियों के लिए आवाज उठाता रहूंगा।

चाहे कमाती है पत्नी फिर भी, गुजारा भत्ते पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मुंबई (एजेन्सी) बंबई उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि एक महिला को अलग रह रहे अपने पति से मिलने वाली वित्तीय सहायता से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कमाती है। न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने 18 जून के आदेश में कहा कि पत्नी उसी जीवन स्तर की हकदार है, जिस तरह का जीवन वह पति से अलग होने से पहले संसुगाल में गुजार रही थी। इस फैसले की एक प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराई गई। अदालत ने एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसे अगस्त 2023 के कुटुम्ब अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। कुटुम्ब अदालत ने व्यक्ति को अपनी पत्नी को 15,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी पत्नी एक कामकाजी महिला है, जो 25,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक कमाती है और इसलिए उसे उससे ‘उच्च गुजारा भत्ते की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि पत्नी कमा रही है, लेकिन यह आय उसके खुद के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसे अपनी नौकरी के लिए रोजाना लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इतनी आय के साथ, वह एक अच्छा जीवन जीने की स्थिति में नहीं है। न्यायमूर्ति देशपांडे ने कहा, “केवल इसलिए कि पत्नी कमा रही है, उसे अपने पति से मिलने वाली आर्थिक सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पत्नी की तुलना में कहीं अधिक कमाता है, जबकि उसकी कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं है।

अहमदाबाद विमान हादसे की गुत्थी अब सुलझेगी, ब्लैक बॉक्स से मिला डेटा

नयी दिल्ली (एजेन्सी) अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे की वजहें जल्द ही सामने आ सकती हैं। दरअसल, दुर्घटना में लगे विमान के ब्लैक बॉक्स की मेमोरी को सफलतापूर्वक एक्सेस कर लिया गया है।

अब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की प्रयोगशाला में इसके डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। सीबीआर और एफडीआर से प्राप्त जानकारी की जांच जारी है। इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि एयर इंडिया की पलाइट एआई-171 के ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए हैं और उनका विस्तृत विश्लेषण चल रहा है। 13 जून को हुई दुर्घटना के बाद, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने महानिदेशक के नेतृत्व में एक बहु-विषयक जांच टीम का गठन किया है। इस टीम में विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी और विमान निर्माता एजेंसी के साथ-साथ अमेरिका स्थित नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (एनटीएसबी) का प्रतिनिधि भी शामिल है।नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीबीआर) और पलाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) दोनों सफलतापूर्वक बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से एक ब्लैक बॉक्स 13 जून को दुर्घटना स्थल की एक इमारत की छत से मिला था, जबकि दूसरा 16 जून को मलबे से निकाला गया। इसके बाद, 24 जून को पूरी सुरक्षा के साथ एआईएफ के विमान द्वारा ये ब्लैक बॉक्स अहमदाबाद से दिल्ली लाए गए। पहला ब्लैक बॉक्स 24 जून को दोपहर दो बजे एएआईबी की लैब, दिल्ली पहुंचा, जबकि दूसरा ब्लैक बॉक्स उसी दिन एएआईबी की दूसरी टीम द्वारा लाया गया। उसी दिन शाम को एएआईबी के महानिदेशक के नेतृत्व में एएआईबी और एनटीएसबी के तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने इन रिकॉर्डर्स से डेटा निकालने का काम शुरू किया, जिसे एएआईबी की लैब में डाउनलोड किया गया।

बिहार में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं : कांग्रेस सांसद तारिक अनवर

नयी दिल्ली (एजेन्सी) बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 40 सीट ऑफर कर रही है। जब इस बारे में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से जवाब मांगा गया तो उन्होंने इस दावे को खारिज करते हुए अफवाह करार दिया। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने गुरुवार को समाचार एजेंसी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर जो भी खबरें सामने आई हैं, वो बिल्कुल झूठ हैं। सीट बंटवारे को लेकर अभी हमारी को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें सबकुछ तय होगा। कमेटी की बैठक में सबकी राय ली जाएगी। हमारा मकसद बिहार चुनाव को लेकर स्पष्ट है कि हमें एनडीए की सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। बिहार में बदलाव लाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। बिहार को एक प्रगतिशील सरकार की सख्त जरूरत है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जल्द ही इसकी तस्वीर आप सभी के सामने होगी। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़े सवाल पर कहा कि इस मामले में पार्टी आगे अध्ययन करेगी। कानूनी तौर पर आगे क्या कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से कुछ चीजों की मांग की गई थी, जब वह मिल जाएंगी तो आगे विचार किया जाएगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारी विदेश नीति फ्लॉप है। दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ हमें समर्थन नहीं मिला है। भारत अलग-थलग पड़ गया है। उसे दूसरे देशों से समर्थन नहीं मिल रहा है।प्रशांत किशोर के दल जनसुराज को स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह मिलने पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि अच्छी बात है कि उन्हें चुनाव चिन्ह मिल गया है। राजनीति में उन्होंने जितना समय दिया है और बिहार में वह प्रचार भी कर रहे हैं। बिहार चुनाव का परिणाम उनका राजनीतिक सफर तय करेगा।

सम्पादकीय

न भूलें आपातकाल थोपने के पीछे का इरादा, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय

कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 से 77 तक लगाया गया आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। उस दौर में इंदिरा सरकार ने संविधान का मूल भावना को दरकिनार कर लोकतंत्र के आत्मा, संवैधानिक संस्थाओं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों पर आघात किया। आपातकाल का कालखंड भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कलक के टीके की तरह है। इस पर काफी चर्चा हुई है। किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन इस पहलू पर उत्तरी चर्चा नहीं हुई कि आपातकाल लगाने के पीछे इंदिरा गांधी की मंशा क्या थी? अगर 1977 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटतीं तो भारत के लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे पर इसके क्या प्रभाव पड़ते? आपातकाल के दौरान किया गया 42वां संविधान संशोधन संविधान के मूल आत्मा को बदलने का एक प्रयास था। इसके मूल में एकदलीय प्रणाली को स्थापित करने की मंशा थी। यह एक तरह से संविधान को ही बदलने का प्रयास था। इस संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम किया गया, नागरिक अधिकारों को सीमित किया गया और इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को असाधारण शक्तियां दे दी। कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड ने अपने संपादकीय में आपातकाल की हिमायत में लिखा था कि समय आ गया है कि अब देश एकदलीय लोकतंत्र की दिशा में बढ़े। इंदिरा के करीबी सहयोगी बीके नेहरू, जो एक अनुभवी राजनयिक भी थे, ने आपातकाल की सलाहना में एक पत्र में लिखा था कि संसदीय लोकतंत्र हमारी जरूरतों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी से आग्रह किया कि अब जब आपके पास दो-तिहाई बहुमत है, तो संविधान में मौलिक परिवर्तन कर डालिए। इसलिए, यह संदेश निराधार नहीं कि यदि इंदिरा गांधी 1977 में सत्ता में वापसी करतीं तो यह प्रक्रिया और तेज होती। संविधान के मूल ढांचे, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय व्यवस्था, नागरिक अधिकार एवं चुनावों की निष्पक्षता को कमजोर करने के लिए और संशोधन लाए जाएं। तब भारत की लोकतांत्रिक पहचान ही खतरे में पड़ जाती। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने असहमत विरोधी दलों पर कड़े प्रतिबंध लगाए, सैकड़ों नेताओं को जेल में डाला और अनेक गैर-राजनीतिक संगठनों की आवाज भी दबाई। इसके पीछे उनका इरादा बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करके देश में एकदलीय प्रणाली को शक्तिशाली बनाने का था। यह अलोकतांत्रिक विचार था। इसके तहत इंदिरा गांधी कांग्रेस को एकमात्र राजनीतिक शक्ति बनाना चाहती थीं।

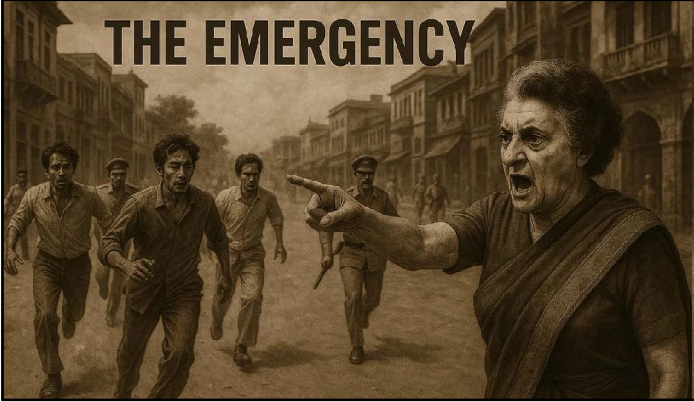
आपातकाल की वक्त भारत में परिवार आधारित तानाशाही का प्रयोग चल रहा था। यदि यह प्रयोग सफल हुआ होता तो देश की निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रणाली के बजाय एक दल-एक परिवार' की व्यक्तिगत इच्छाओं से संचालित होती। आपातकाल में नौकरशाही को कांग्रेस पार्टी के एजेंडे के प्रति वफादार बनाने के सारे प्रयास हुए। योग्यता और निष्पक्षता को दरकिनार कर केवल वफादारी के आधार पर पदोन्नति दी गई। एक समर्पित नौकरशाही की परिकल्पना भी आपातकाल के दौरान उभरी। यदि 1977 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती, तो पूरी आशांश की थी कि इस नीति को और आक्रामक रूप से लागू किया जाता। स्वतंत्र प्रशासनिक संस्थाएं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कैंग, चुनाव आयोग को निष्प्रभावी बनाया जाता और एक 'कमिटेड ब्यूरोक्रेसी' तैयार की जाती। कांग्रेस द्वारा समय-समय पर ऐसी कोशिश की जाती रही है, इसलिए इस संस्था को बल मिलता है। देश में लोकतंत्र की आंधर सहीला रखने वालों ने स्वतंत्र और स्वायत्त न्यायपालिका की व्यवस्था दी थी। उसे भी इंदिरा सरकार ने सरकार के प्रति प्रतिबद्ध बनाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता की अनेदृष्टि कर कनिष्ठ जज को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस एचआर खन्ना जैसे साहसी न्यायाधीशों को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने नागरिक अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया था। यदि इंदिरा सत्ता में कायम रहती तो न्यायपालिका पर दबाव और बढ़ता। संवैधानिक समीक्षा की शक्तियों को सीमित किया जाता, न्यायिक नियुक्तियों में सरकार की मनमानी चलती और अदालतें सरकारी एजेंडे को वैध ठहराने का माध्यम बन जाती। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर अन्तर्पूर्व हमला हुआ। व्यापक संसेरशिप लगाई गई। सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाया गया। कई समाचार पत्रों के मालिकों, संपादकों को दंडित किया गया, क्योंकि उन्होंने आपातकाल की आलोचना की थी। कुछ अखबारों ने अपने संपादकीय खाली छोड़ दिए थे।

सवालों में संघर्ष विराम

सवालों और सशय के बीच इजरायल—ईरान के बीच छिड़ भीषण युद्ध पर विराम लग गया। इस युद्ध में अमेरिका ने कट्टर और ईरान के परमाणु टेकराकों को निशाना बनाकर पश्चिम एशिया के साथ विश्व शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया था। फिलहाल यह खतरा तलता दिख रहा है, लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि इजरायल—ईरान के बीच की घड़ियालों पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी और ऊर्जा के स्रोत वाले पश्चिम एशिया में शांति भी आ जाएगी, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। उनकी किसी बात पर भरोसा करना ठीक नहीं। वह अपनी ही बात और अपनी ही नीति से पलट जाते हैं। अब वह बीच—बचाव की मुद्रा में प्रवेश रहे और इजरायल को भी नसीहत दे रहे हैं। उनकी और इजरायल की प्रधानमंत्री की मानें तो ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता खो दी है, लेकिन ईरान कह रहा है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। क्या वह परमाणु हथियार हासिल करने का इरादा सचमुच छोड़ देगा? क्या उसके बच्चे—खुचे विज्ञानी यह विस्मृत कर सकते हैं कि परमाणु हथियार बनाने कैसे हैं? क्या अमेरिका से सदा सशक्तित रूस और चीन भी यह चाहेंगे कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का इरादा छोड़ दे? स्पष्ट है कि ऐसे सवालों का जवाब भविष्य ही देगा। इस पर हैरानी नहीं कि ईरान भी अपनी जीत और शत्रु को सबक सिखाने का दावा कर रहा है। ऐसा ईरानी जनता और खास तौर पर कट्टर मजहबी सत्ता के समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दिख रही रहा है कि जिस तरह भारत के आपरेशन सेंडूर से पाकिस्तान परत हो गया था, वैसे ही, बल्कि उससे ज्यादा इजरायल और अमेरिकी सेनाओं के सामने ईरान भी परत हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी ने खूब गर्जन—तर्जन किया और उनकी सेनाओं ने इजरायल को कुछ नुकसान पहुंचाने के साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी के टिकाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसी क्रम में कतर, इराक आदि में अमेरिकी अड्डों को निशाना भी बनाया गया, लेकिन ये कुलमिलाकर निष्पत्ती हमले थे। ईरान ने ये हमले कर एक तरह से अपनी जीख मिटाई। वास्तव में उसे इन हमलों के बहाने संघर्ष विराम की ट्रंप की शर्तशक स्वीकार का जरिया मिल गया। ऐसा कोई जरिया उसके लिए जरूरी भी था, क्योंकि कोई देश यह नहीं कहता कि वह असहाय हो गया। इसका एक उदाहरण पाकिस्तान है, जिसने भारत से हमेशा पिटने के बाद भी अपनी जीत का दावा किया। चूंकि भारत के ईरान और इजरायल, दोनों से संबंध हैं, इसलिए उसने किसी एक पक्ष में खड़े न होकर सर करी किया। भारत को सबसे पहले अपने हित ही देखने चाहिए। वर्तमान वैश्विक हालात और ईरान ट्रंप के रथे को देखते हुए तो ऐसा करना और भी आवश्यक है। क्या वह परमाणु हथियार हासिल करने का इरादा सचमुच छोड़ देगा? क्या उसके बच्चे—खुचे विज्ञानी यह विस्मृत कर सकते हैं कि परमाणु हथियार बनाने कैसे हैं? क्या अमेरिका से सदा सशक्तित रूस और चीन भी यह चाहेंगे कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का इरादा छोड़ दे? स्पष्ट है कि ऐसे सवालों का जवाब भविष्य ही देगा। इस पर हैरानी नहीं कि ईरान भी अपनी जीत और शत्रु को सबक सिखाने का दावा कर रहा है। ऐसा ईरानी जनता और खास तौर पर कट्टर मजहबी सत्ता के समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दिख रही रहा है कि जिस तरह भारत के आपरेशन सेंडूर से पाकिस्तान परत हो गया था, वैसे ही, बल्कि उससे ज्यादा इजरायल और अमेरिकी सेनाओं के सामने ईरान भी परत हो गया। इसी क्रम में कतर, इराक आदि में अमेरिकी अड्डों को निशाना भी बनाया गया, लेकिन ये कुलमिलाकर निष्पत्ती हमले थे।

नीरज कुमार दुबे

दश 25 जून, 1975 का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में लागू गये आपातकाल की 50वीं बरसी मना रहा है। मोदी सरकार आपातकाल की अवधि के दौरान अमानवीय पीड़ा झेलने वालों के व्यापक योगदान को याद करने के लिये आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है ताकि दूसरी ओर राजनेता हों या मीडियाकर्मी अथवा सामान्य जनसभी उस दौर को याद कर कांग्रेस को कोस रहे हैं क्योंकि वह देश की सरकार द्वारा अपनी ही जनता पर किये गये अत्याचार की निरमर परकाष्ठा थी। उस समय देश में एक लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में दंड दिया गया था। देश के जितने भी बड़े विपक्षी नेता थे, सभी के सभी सलाखों के पीछे जाल दिए गए थे। राजनीतिक बंदियों की अपने परिवारों से मुलाकात तक पर पाबंदी लगाने की गई थी। नेता ही नहीं अदालतों भी एक तरह से कैद हो चुकी थीं। किसी को जमानत नहीं दी जा रही थी और मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतः सॉझान कार्रवाई जा रहा था। राजनीतिक कार्यकर्ता जेल में मानसिक-शारीरिक यातनाएं सह रहे थे। पुलिस हिरासत और जेलों में मौत हो रही थीं लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। हम आपको बता दें कि देश में आपातकाल के 1975 में अधिकारी रूप से लागू होने से पहले, ग्राभीण इलाकों में छोटे बच्चे अवसर बिना कपड़ों के बेफिक्री से दौड़ते-भागते नजर आते थे। लेकिन आपातकाल के दौरान हालात इतने भयावह हो गए थे कि लोगों ने मासूम बच्चों को भी कपड़े पहनाने शुरू कर दिए थे, यह शालीनता की भावना से नहीं हो रहा था बल्कि जबर्न नसबंदी की आशंका से उजड़ा डर था, जिसने पूरे समाज को जकड़ लिया था। सामूहिक नसबंदी अभियान की यादें आज भी जीवित बचे पीड़ितों को परेशान करती हैं क्योंकि कई लोगों की नसबंदी जबर्दस्ती की गई थी। अकेले 1976 में, पूरे भारत में 80 लाख से अधिक लोगों की नसबंदी की गई थी। इनमें से ज्यादातर पुरुष थे, जिनमें से कई लोगों की नसबंदी स्वेच्छिक नहीं थी। हम आपको बता दें कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तानाशाह इसलिए बन गयी थीं और देश पर आपातकाल इसलिए आरोप दिया था क्योंकि एक पुराना मामला राजनीतिक रूप से उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सबब बन गया था। दरअसल 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध में इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण



को रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणामामान्य आने के चार साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उन्होंने दलील दी थी कि कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, चुनाव में मैं तय सीमा से अधिक पैसे खर्च करके और मवादताओं को प्रभावित करके ए लिए गलत तरीकों व इस्तेमाल किया। मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय को न 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को आरोपों में दोषी पाया और छह साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। राजनारायण इंदिरा गांधी के चिर प्रतिद्वंद्वी विजयी घोषित कर दिया था। अनुचित के इस फैसले ने देश में बड़ा साक्ष्य। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशां को बरकरार रखा, हालांकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के इजाजत दे दी। इस फैसले वहाँ इंदिरा गांधी बौखला गयी थीं। अपने खिलाफ विपक्ष की एकजुटता और विरोध प्रदर्शन बढ़ते देख इंदिरा गांधी ने 25-26 जून की रात को आपातकाल लगाने का फैसला किया। और रात्रि को ही राष्ट्रपति फख्रुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ ही भारत में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियोसुन पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपतिजी ने आपातकाल की घोषणा की है। लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को आपातकाल का मतलब तब समझ आया जब उन्हें पता चला कि उनके पास सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित करके सरकार विधेी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध दिया गया है। इससे जनता नाराज हुई और सड़कों पर उतरने वाले

पर शस्त्र को जेलों में दूँस दिया गया था। हम आपको बता दें कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में कुल 48 अध्यादेश लागू किए थे जिसमें आंतरिक सुरक्षा कानून अतिनियम (मिसा) में संशोधन के लिए लागू गए पांच अध्यादेश भी शामिल थे। प्रशासन को बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर का अधिकार देने वाले इस कानून को अक्सर 'दमनकारी' कानून की संज्ञा दी जाती है। पचास वर्ष पहले 25 जून 1975 को लागया गया आपातकाल 21 महीने जारी और इस दौरान सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव किए जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया तथा संविधान की प्रस्तावना में 'रसमाजवादीश्, श्रमनिरपेक्षश् और श्रमखंडताश् जैसे शब्द जोड़े गए। संविधान कानूनों में संशोधनों से सत्ता विभुल कर देकर सरकार के पक्ष में हो गया और न्यायपालिका की शक्तियों में में कटौती कर दी गई। देश में आपातकाल लागू होने पर कुछ ही दिनों के भीतर 29 जून 1975 को सरकार ने मिसा में बदलाव करने के लिए पहला अध्यादेश जारी किया था। आपातकाल के दौरान मिसा (संशोधन) अध्यादेश को और चार बार लागू किया गया तथा संसद द्वारा उसमें मंजूरी दे दी गई। अगले ही दिन राष्ट्रपति फख्रुद्दीन अहमद ने एक अध्यादेश भारत रक्षा अतिनियम (संशोधन) लागू किया, जिससे सरकार को देश में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज्यादा शक्तियां मिल गईं। आपातकाल के दौरान संसद के संक्षिप्त सत्र आयोजित किए गए। विपक्ष के कई नेता सलाखों के पीछे थे और कांग्रेस ने अपने प्रचंड बहुमत का इस्तेमाल करते हुए कई अध्यादेशों पर संसदीय मांहर लगावने के लिए मसौदा विधेयक को पारित कर दिया गया था। उस दौर के बारे में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने बताया कि

न्होंने दलील दी थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी शीनरी का दुरुपयोग किया, चुनाव में तय सीमा से अधिक खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मत तरीकों का इस्तेमाल किया। मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को आरोपों में दोषी पाया और छह साल के लिए पद से बंद रख कर दिया तथा इंदिरा गांधी के विरुद्ध द्वि-राज नारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था। अदालत के इस फैसले ने देश में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था।

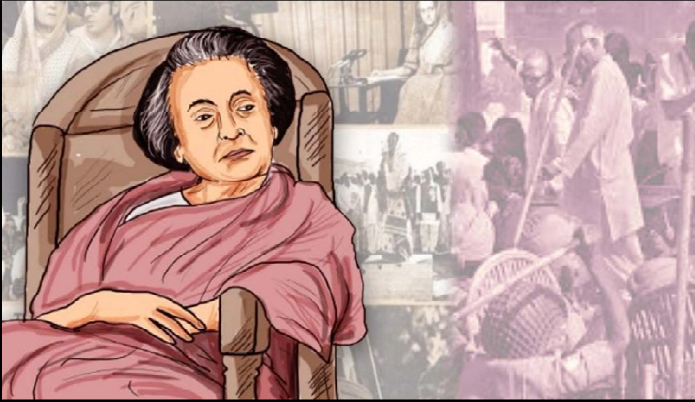
जब आपातकाल घोषित किया गया तो कुछ पुलिसकर्मियों ने रात में हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। जब वे मेरे पिता को गिरफ्तार करने आए तो हमने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि वे (इंदिरा) गांधी को कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। हमने सोचा कि वे उन्हें गिरफ्तार करेंगे और कुछ दिनों में रिहा कर देंगे। लेकिन अगली सुबह हमें पता चला कि देश में आपातकाल लगा दिया गया है। उस समय दिवंगत अरुण जेटली दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के अध्यक्ष थे। विजय गोयल ने न कहा कि वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा और वह दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहें थे। विजय गोयल ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि वह किस तरह पुलिस से बचने के लिए छतों से कूदकर भाग रहे थे। कैसे लोगों को जेलों में प्रताड़ित किया गया। उन्होंने बताया कि वे लगातार अपना टिकाना बदलते रहते थे और अक्सर पुलिस से बचने के लिए छुले में सोते थे।

उन्होंने बताया कि अंत में पार्टी नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों में शामिल लोगों को सम्मर्पण करने की सलाह दी। उस समय तक रजत शर्मा पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। उन्हें पीटा गया लेकिन रजत शर्मा ने विजय गोयल के ठिकाने को लेकर जुबान नहीं खोली। विजय गोयल ने बताया कि कैदी अक्सर खराब भोजन को लेकर थालियाँ बजा बजाकर विरोध जताते थे और इसके लिए उन्हें पीटा जाता था। बीमार कैदियों को पैराल नहीं दी गई। लेकिन पुलिस स्टेशन में जेलों के मुकामले कहीं-कहीं ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती थी। लेकिन ऐसे माहौल में भी हॉस्टल बुलंद रखने के लिए कैदियों द्वारा कविता पढ़ने, पेंटिंग और बैडमिंटन प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती थीं। उन्होंने बताया कि आपातकाल ने ना जाना किन्ती ज़िदगियों को तबाह कर दिया। लोगों को भयानक तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। उनके बाल और नाखून खींचे जाते थे, बर्फ की सिलियनों में लिटायी जाता, महिलाओं को भी यातन-प

दी जाती थी। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व प्रचारक और संस्थापक अध्यक्ष श्री आरजीनंद के आचार्य राजनीति के विचार को केएस गोविंददाचार्य ने आपातकाल को 'अशुभ' करार देते हुए कहा कि इस दौरान आरएसएस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा के पूर्व पदाधिकारी ने कहा कि सच परिवार ने उस आंदोलन को थिथराता है। उन्होंने कहा, 'समय के माध्यम से दोषानुसंधान कायम रखने के लिए जिस प्रकार कर्म ने बासुकी नागा और मंदयावल पर्वत के साथ एक भूमिका अदा की, आपातकाल में वही भूमिका सच की थी।' वहीं उस दौर में मीडिया की भूमिका को देखते हुए तो समाचार पत्रों पर संसारीपत्र, पत्रकारों की गिरफ्तारी और समाचार एजेंसियों का विनय, ऐसे ही कुछ तरीकों से इंडिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आपातकाल के 21 महीनों के दौरान सार्वजनिक विमर्श को निर्यतित कराने की कोशिश की थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आपातकाल के दौरान सरकार के हिसाब से काम करने से इंडिका करने वाले 200 से अधिक पत्रकारों को विपक्षी नेताओं के साथ जेल में डाल दिया गया था। इसके अलावा ही सरकार ने चार समाचार एजेंसियों— प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती की विमल व्यवस्था करके एक समाचार एजेंसी 'समाचार' बना दी थी। उस समय सरकार ने समाचार रिपोर्टिंग पर कड़ी निगरानी रखी थी और पत्र सूचना कार्यालय (पीआईसी) में तैनात एक आईपीसी अधिकारी ने यह सुनिश्चित किया कि खबरों में सरकार के पक्ष में ही खबरें पहुंचें। पत्रकारों को संज्ञा गांधी और पुरुषों की जबन नसबंदी द्वारा से जुड़े उनके प्रचार निषेधन कार्यक्रमों पर प्रसारण करने तथा विपक्ष से संबंधित खबरों को कुछ पैराग्राफों में समेटने के लिए मजबूर किया जाता था। वरिष्ठ पत्रकार एस वैकनाथन आपातकाल के दौरान अश्विनलुकर पत्रिका के संपादक थे। विजय गोयल ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा और वह दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष प्रदर्शनों में शामिल रहे थे।

अब रेयर अर्थ को लेकर दुनिया में खींचतान होगी

बदल देना दो दिन की बातचीत व बाद अमेरिका और चीन पिछले महीने जेनेवा में हुए व्यापार सौदे के तहत पर एक नए सौदे पर सहमत हो गए। जिनपिंग और ट्रम्प की फोन पर बातचीत के बाद जेनेवा समझौता हुआ। लेकिन अमेरिका ने इसका कंपनी की कुछ एसेन्ड चिप्स का उपयोग लिबिबत कर दिया था जिसके कारण जेनेवा सौदा रद्द कर दिया गया। प्रतिक्रिया में चीन ने दुनियाभर में हाईटेक उत्पादों में कार्रवाई करते रथर सौदे पदाओं के न्याय सौमिल कर दिया। अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई में चीनी विद्यार्थियों के वीजा वापस ले लिए थे। तब जाकर ट्रम्प और जिनपिंग ने वीजा सप्ताह 90 मिनट बात की और फिर लंदन समझौता हुआ। अब, ट्रम्प व चीन ए टीवी के अनुसार दोनों पक्षों बीच चिन बातों पर सहमत नहीं हैं। उनमें टैरिफ घटा कर चीन पर 30 प्रतिशत और अमेरिका पर 10 प्रतिशत किया जाएगा। अमेरिका चीन को कार्मेक एयरलाइनर के पुर्जों का सप्ताई समेत कुछ तकनीकी प्रतिबंधों को हटा सकता है। दोनों पक्षों का आशा है कि इससे उनके बीच चल रहे ट्रेड वॉर में शांति आएगी और कई मुसीबतों से जूझ रही उनकर इस्तेवस्थाओं को बल मिलेगा। लेकिन इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका और चीन के बीच मौजूद समस्या की जड़ में रथर अर्थ और मैनेन्ट का मसला है। रथर अर्थ मैनेन्ट सामान्य आयरन मैनेन्ट 20 गुना अधिक ताकतवर होता है और कारों तथा कई अन्य उपकरणों में लगने वाली इलेक्ट्रिक मोटोर्स में बनाने के लिए जरूरी है। 17 प्रकार की धातुओं को रथर अर्थ के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं कि रथर दुर्लभ है, ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ चीन में ही ऐसे भंडार हैं, जहां आसानी से इनका खनन किया जा सकता है। चीन व पक्ष ही इनकी प्रोसेसिंग की क्षमता है। चूंकि इन तत्वों को एक-दूसरे से अलग करना मुश्किल है, इसीलिए इन्हें रथर कहा जाता है। इनका अलग करने की जटिल प्रक्रिया में भारी मात्रा में एसिड की जरूरत होती है। रथर अर्थ की वैश्विक सप्लाई घेने में चीन का दबदबा है। इनका 70 प्रतिशत खनन और 90 प्रतिशत प्रोसेसिंग अकेला चीन करता है। रथर विंड टर्बाइन, राकॉन उपकरणों और इलेक्ट्रिक वहां से लेकर हर चीज में काम आते हैं। आधुनिक इंडस्ट्री में इनका महत्व यों समझा जा सकता है कि जैसे ही चीन ने रथर अर्थ को मैनेन्ट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए, भारत में सुजुकी कंपनी को अर्धनियोजित कारों के लिए मजबूर होना पड़ा। विश्व की अन्य कार कंपनियों को भी प्रेशानी झेलनी पड़ी। अप्रैल में जब ट्रम्प ने इससे लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा की तो चीन ने सात प्रकार की रथर अर्थ धातुओं तथा इनका बनने वाली सुपर पावरफुल मैग्नेट का निर्यात रोक दिया, क्योंकि रथर चीजें सैन्य और नागरिक, दोनों प्रकार के उपयोग में आती हैं। 2010 में जापान से सीमा विवाद के बाद भी चीन ने इनका निर्यात रोक था। रथर रथर अर्थ की आपूर्ति बहाल करने में चीन की धीमी गति के कारण हैं जेनेवा समझौता टूट गया था। अतः रथर रथर अर्थ मैनेन्ट निर्याडिमिथम और प्रेसिडिडिमिथम से बनी होती है। इसमें डायसप्रोसिथम और टर्बिथम मिलाएँ तो यह मैनेन्ट ताप के प्रति और अधिक प्रतिरोधी बन जाता है। रथर रथर अर्थ का निर्यात चीन ने रोक र, उनमें सैमेरिथम का उपयोग इंटर कॉन्टिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम में होता है। लड़ाकू विमान एफ-35 में कर के किलोग्राम सैमेरिथम काम आता है। यडिथम का उपयोग लेजर बनाने और स्कैंडियम का उपयोग हल्के विमानों के पुर्जे बनाने में होता है। लेकिन इन तत्वों का सैन्य उपयोग महज 5 प्रतिशत ही है। भारत को भी कहीं न कहीं विंड टर्बाइन, मिसाइल गाइडेंस और सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में आर्कनिभरता के लिए रथर अर्थ तत्वों की जरूरत है। 2023-24 में हमने 2270 टन रथर अर्थ आयात किया था। इसमें अधिकतर हिस्सा रथर से आया था। भारत में भी रथर अर्थ के भंडार हैं, जो वैश्विक भंडार के लगभग 6 प्रतिशत हैं। केरल में थोरियम सैंड के अलावा आंध्रप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में भी इसके भंडार हैं। लेकिन दुनियाभर की आपूर्ति का उथ्पादन प्रतिशत हिस्सा ही भारत में उथ्पादित होता है। रथर अर्थ के लिए चीन पर निर्भर होना सही नहीं होगा क्योंकि इससे उसे हम पर प्रभावी चीन का मौका मिलता है। अब यह जरूर है कि भारत अपने स्तर पर इनका उत्पादन शुरू करे और अन्य देशों में भी खनन की संभावनाएं देखे। (लेखक के अपने विचार हैं)



मेरा चतुर्वेदी
मोदी सरकार को कठघरे में
खड़ा करते वक्त विपक्षी दल एक
आरोप बार-बार लगाते हैं। उनका
कहना है कि देश पर इन दिनों
अधोषिठ आपातकाल लागू है।
अदिलचस्प यह है कि यह आरोप
लगाने वाले दलों में कांग्रेस भी शामिल
है। स्वाधीन भारत के इतिहास में
इसका अर्थ अतः अत्यंत ही दुःखदायक
आपातकाल को आज ही के दिन
आधीक पचास साल पहले इंदिरा गांधी
जी की अगुआई वाली सरकार ने देश
पर थोप दिया था। इसके बाद जैसे
समूचा देश ही जेल के रूप में
तब्दील हो गया था। सरकारी आंकड़ों
के अनुसार, करीब 35 हजार लोग
मिस्रीसा और लगभग 75 हजार लोग
डीडीआरआई के तहत गिरफ्तार कर
लिया गए। न्यायपालिका के अधिकारों
सीमित कर दिए गए। जबदस्ती
नसबंदी कराई जाने लगी। दिल्ली
के तुरुमान गेट की सफाई करने के
लिए पर बुलडोजर चलाकर कई
घर जमींदार कर दिए गए। विरोध
कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोशिया
चलाई। उस गोलीबारी में कितने
आज तक अधिकारिक आंकड़ा जारी
नहीं किया है। अधोषिठ आपातकाल
आरोप जब कांग्रेस लगाई है तो
अपनी इस गलती को अब तक वह
सर्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं
कर पाई है। आपातकाल के दौरान

जलों में बंद रहे लोगों के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गैर कांग्रेसी सरकारों ने पेंशन की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही इन राज्यों में कांग्रेसी सरकार आई, उन्होंने यह पेंशन बंद कर दी। इसका मतलब यह है कि वह आपातकाल को अब तक सही ही मानती है। अगर वह गलत मानती तो निश्चित तौर पर पेंशन को जारी रखती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकारें लौट आई हैं, लिहाजा वहां एक बार फिर पेंशन शुरू हो रही है, लेकिन कर्नाटक में अब भी पेंशन बंद है। जाहिर है कि ऐसा करके कांग्रेस मानती है कि आपातकाल सही था। अगर वह सही था तो फिर देश में अघोषित आपातकाल की चर्चा में उतराया जा सकता है। आपातकाल क्यों लगा, इस दौरान सरकार ने संविधान के तहत मिले ज्यों के अधिकार तक को मुलतवी क्यों कर दिया? इन सवालों के जवाब बार-बार दिए जा चुके हैं। बारह जून 1975 को दो घण्टाएं हीली घटी, जिसने इंदिरा गांधी को ऐसा दिया। इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के रायबरेली के चुनाव में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के आरोप को सही पाते हुए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही हीली दिन गुजरात में कांग्रेसी विमन भाई पटेल की सरकार बनायीं।

सुप्रीम कोर्ट ने सिन्हा के फैसले पर रोक तो लगा दी, लेकिन इंदिरा गांधी को संसद में वोटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया। इसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह पर 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर से देश पर आपातकाल थोप दिया गया। हैरत की बात यह है कि इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखा गया। कैबिनेट की मंजूरी के बिना सीधे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करा लिया गया और कैबिनेट की रस्मी बैठक अगले दिन यानी छब्बीस जून को हुई। दिलचस्प यह है कि नियम-प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए समूचे देश को जेल बना देने वाले आपातकाल को गांधी जी के रचनात्मक शिष्य विनोबा भावे ने अनुशासन पर्व कहा था।

पर गई इसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि उनकी सत्ता को बड़ी चुनौती मिली है। बेशक सिन्हा ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए बीस दिनों का समय दिया, लेकिन इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने इस फैसले से बचाव का समानांतर रास्ता खोज लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिन्हा के फैसले पर रोक तो लगा दी, लेकिन इंदिरा गांधी को संसद में वोटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया। इसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह पर 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद के हस्ताक्षर से देश पर आपातकाल थोपा दिया गया। हैस्ट की बात यह है कि इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखा गया। कैबिनेट की मंजूरी के बिना सीधे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कर लिया गया और कैबिनेट की रस्मी बैठक अगले दिन यानी छब्बीस जून को हुई। दिलचस्प यह है कि नियम-प्रक्रिया को उल्लंघन करने हुए समूचे देश को जेल बना देने वाले आपातकाल को जेल बना देने के रचनात्मक शिष्य विनोबा भावे ने अनुशासन पर्व कहा था। आपातकाल की पूर्व पीठिका में गुजरात से शुरू छात्रों के आंदोलन का पहले विहार पहुंचना, उसमें जयप्रकाश नारायण का कूदना और सत्ता के सत्तक उनका व्यवस्था बदलने की अपील करना जैसी बड़ी वजहें रही। इक्कीस महीने तक देश पर लागू रहे आपातकाल ने लाखों लोगों को जैसे पिंजरे में कैद कर दिया। पलिस की निरंकुशता

बड़े गद्दी। न्याय व्यवस्था पंगु हो गई। नौकरशाही हावी रही। इंदिरा गांधी की कंधे के छोटे बेटे संजय गांधी की शह पर मनमानियां हुईं। प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी गई। इसकी वजह से सहज के तथ्य सामने नहीं आ पा रहे थे। देश के तमाम विपक्षी नेता जेलों में दूंस दिए गए। इक्कीस महीने बाद जब आपातकाल हटा और देश में चुनाव हुए तो समूचे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया। इंदिरा गांधी की सहयोगी रहीं पुपुल जयकर ने लिखा है कि आपातकाल के आखिरी दिनों में इंदिरा गांधी आध्यात्मिक गुरु जे कृष्णमूर्ति से मिलीं। उसके बाद उन्होंने न देश से आपातकाल हटाने और चुनाव कराने का फैसला लिया। आपातकाल के बाद 1977 के आम चुनावों में विपक्षी दलों के मोर्चे जनता पार्टी ने चुनाव जीता और देश से आपातकाल की काली छाया हटी। इंदिरा और उनकी कांग्रेस को कीमत चुकानी पड़ी। उनकी संसदीय लाज दक्षिण के राज्य में नहीं रखी। आपातकाल का एक संदेश यह है कि अब कोई भी सरकार बनने में दोबारा आपातकाल लागू करने की कोशिश नहीं कर सकती। अघोषित आपातकाल के आरोपों का नाम दूबारा सामना करने वाले प्रजापान्थी मोदी कोई बार इस तथ्य को दोहरा चुके हैं। आपातकाल ने देश को अनुशासन में कितना ढाला, इससे लेकर शोध हो सकता है। लेकिन यह सच है कि घोषित तौर पर उसने नागरिक अधिकारों की हत्या

हैं। भारत में चाहे जो भी शासन-
तंत्र रहे हों, लेकिन जीवन के अंश
कांकर को राज सत्तन में बंभी अस्वीकार
नहीं किया। लेकिन इंदिरा सरकारा
ने ऐसा किया। आपातकाल के
दूसरा संदेश यह है कि तानाशाही
वाली राजनीति लोकतांत्रिक समाज
में नहीं चल सकती। राजनेता क
जनता के सामने झुकरा पड़ेगा
अथवा, उसका हथ इंदिरा जैसा ही
होगा। यह बात और है कि महज
ढाई साल पहले राजनीति के
खलनायिका बनी इंदिरा को इस
देश की जनता ने सिर आंघों प
बैठाया। उनकी तानाशाही को महज
ढाई साल बाद ही मूल राई और
1980 के चुनावों में देश की सत्त
सौंप दी। आपातकाल ने देश क
व्यवस्था परिवर्तन का मौका दिख
जा। जनता ने विपक्षी खेमे को सत्त
इसी बदलाव की उम्मीद के साथ
सौंपी थी। लेकिन वह महज सत्त
परिवर्तन रहा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं
उसी दौर के उभरने पर तानाशाही
जातिवादी राजनीति के महान पैरोका
बन चुके हैं। उन पर भ्रष्टाचार और
कदाचार के गंभीर आरोप लगते र
हैं, उन्हें सजाए हुई हैं। वे आज ब
और व्यापक भारतीय समाज क
बुजाय अपनी जातियों के नेता ब
हुए हैं। चंद्रशेखर ने जेपी को उन्नी
आंदोलन के दौरान एक निष्प
लिखकर चेताया था कि जो नेत
उनके साथ आ रहे हैं, दरबसल
व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं, सत्त
की चाहत के लिए आ रहे हैं।

जेल में बंद युवक की संदिग्ध हालात में मौत

सतरिख थाना पुलिस ने 22 जून को आकाश को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा था



बाराबंकी (संवाददाता)। जानलेवा हमले के आरोप में वारंट जारी होने के बाद जेल भेजे गए एक युवक की 36 घंटे बाद ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही बरतने और सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया है। तनाव

कई अपराधिक मामले दर्ज थे। हाल ही में एक जानलेवा हमले की पेशी में न जाने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। सतरिख थाना पुलिस ने 22 जून को आकाश को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल प्रशासन के अनुसार 23 जून की शाम आकाश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। प्राथमिक इलाज के बाद भी जब सु

पहुंचीं, तब तक आकाश की मौत हो चुकी थी और उन्हें बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। परिजनों का आरोप है कि आकाश की मौत की सूचना उन्हें चार घंटे की देरी से दी गई। बताया कि उसके चेहरे पर भी हल्की चोट के निशान मिले हैं। आशंका जताई कि जेल में उसके साथ मारपीट की गई है।उनका कहना है कि आकाश के साथ जेल में कुछ गलत हुआ है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। वहीं जेलर संतोष तिवारी ने बताया कि आकाश गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसे दौरे पड़ते थे। जेल में मौजूद चिकित्सकों का कहना है कि आकाश की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। पुलिस ने मृतक के परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें बेटे की हालत बिगड़ने की सूचना समय से नहीं दी गई। जब वह जिला अस्पताल

जंगली जानवर दिखने पर वन विभाग को सूचना दें ग्रामीण

सीतापुर (संवाददाता) ।। मानव-वन्य जीव संघर्ष का मुख्य कारण वन क्षेत्र में मनुष्य का अतिक्रमण है। इस संघर्ष को रोकने के लिए जन जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। यें बातें सब डिवीजनल फॉरेस्ट अफसर विकास कुमार यादव ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में चल रही कार्यशाला में कहीं।उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर वन्य जीव मनुष्य पर हमला नहीं करते हैं लेकिन ऐसे अनेक कारण हैं जिससे यह मनुष्य के क्षेत्र में भी आने लगे हैं। ऐसे में अगर कोई घातक वन्य जीव दिखाई दे तो ग्रामीण इसकी तुरंत सूचना वन विभाग को दें। वनकर्मी तत्काल उस क्षेत्र में पहुंचकर समस्या का हल निकालेंगे।उन्होंने इस समस्या के निदान के लिए विद्यालयों और ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम करने पर बल दिया। अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं बताईं जिनका वन अधिकारियों ने निदान बताया।



सीतापुर (संवाददाता) रामपुर मथुरा (सीतापुर)। बाढ़ के पानी में फंसकर डूब रहे व्यक्ति को बचाने का पूर्वाभ्यास बृहस्पतिवार को किया गया। अस्पताल लाकर इलाज किए जाने के तौर-तरीके भी दर्शाए जाएंगे। इसके लिए कस्बा स्थित मैदान में अस्थायी अस्पताल बनाया गया है।

एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की तैयारियां पूरी हो गई हैं।बृहस्पतिवार को बाढ़ से राहत व बचाव को लेकर मॉकड्रिल होगी। सरयू नदी की भीषण बाढ़ व कटान से प्रतिवर्ष भारी नुकसान होता है। इस आपदा से होने वाले नुकसान से बचाव या नुकसान को कम करने के लिए प्रशासन ने चाक-चौबंद

रिनफर डॉग ने बढ़ाई अनहोनी की आशंका और पुलिस की चिंता

संदिग्ध हालात में खजोहना गांव से तीन साल का मासूम लापता हो गया, तलाश में जुटी पुलिस



हरदोई (संवाददाता)। संदिग्ध ा हालात में कछौना कोतवाली क्षेत्र के खजोहना गांव से तीन साल का मासूम लापता हो गया। उसकी तलाश के लिए उन्नाव से डॉग स्क्वायड बुलवाया गया। रिनफर डॉग ने मासूम के कपड़ों की गंध लेने के बाद 150 मीटर दूर नहर तक दौड़ लगाई। नहर में जाने के बाद रिनफर डॉग काफी देर तक वहीं रुक गया। रिनफर डॉग से मिले संकेतों से पुलिस की चिंता के साथ ही अनहोनी

की आशंका भी बढ़ गई। खजोहना निवासी गुड्डू जरदोजी करते हैं। परिवार में पत्नी हिना, पुत्र अरहन (3) और नौ माह का एक पुत्र है। गुड्डू के मुताबिक मंगलवार को सुबह साढ़े नौ बजे हिना ने अरहन को नहलाया था। इसके बाद अरहन मकान के बाहर खेलने चला गया। कुछ देर बाद वह वापस नहीं आया तो परिजनों ने तलाश शुरू की। कोई सुराग न मिलने पर दोपहर बाद साढ़े तीन बजे पुलिस को सूचना

दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नुपेंद्र ने कछौना कोतवाली में ही डेरा डाल दिया। मौके का निरीक्षण करने के बाद सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस के जरिये बच्चे की तलाश कराई गई। देर रात उन्नाव से रिनफर डॉग बुलवाया गया। गुड्डू के घर में कुछ देर रुकने के बाद डॉग घर से लगभग 150 मीटर दूर से निकली

तहसीलों में अलग शिकायतें मिली... मानी जाएगी लापरवाही

गोरखपुर (संवाददाता)। सीएम तक पहुंचने वाली जमीन विवाद की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए डीएम ने नई पहल की है। इसके लिए लेखपालों को सभी गांवों के भूमि विवाद रजिस्टर बनाने और थाना स्तर पर इसका निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। इसकी मॉनिटरिंग डीएम खुद करेंगे। स्थानीय स्तर पर इन शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर फरियादी सीएम के जनता दर्शन कार्यक्रम तक पहुंचते हैं और वहां अधिकारी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मामले में फरियादियों को न रोक पाने पर हाटा एसडीएम ने कानूनगो और तीन लेखपालों पर कार्रवाई की थी। जानकारी होने पर डीएम ने कार्रवाई शुरू करने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं तो मंडल के अन्य जिलों के लोग भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। इसके लिए जिलों से भी तहसीलदार, राजकर्मियों की उछटी लगाई जा रही है, ताकि शिकायतकर्ता के वास्तविक मामलों की जानकारी हो सके।

बाग में मिला युवती का शव, प्रेमी पर हत्या का आरोप

बाराबंकी (संवाददाता)। रामनगर कोतवाली क्षेत्र के तालपाल पुरवा गांव में बुधवार सुबह बाग में युवती का शव संदिग्ध दशा में मिला। शव नीम के पेड़ के सहारे ऐसे टिका था जैसे युवती बैठी हो। उसके मुंह से खून निकल रहा था, साथ ही गले में चोट के निशान भी मिले हैं। परिजनों ने युवती के प्रेमी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने के साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।तालपाल पुरवा निवासी मुन्नालाल के मुताबिक उनकी तीन बहनें हैं। माता-पिता का निधन हो चुका है। दूसरे नंबर की बहन नीरज कुमारी (30) ने भी इसकी पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।घार बेटियों के सिर से उठा पिता का साया आकाश ने गैर समुदाय की एक युवती से प्रेम विवाह किया था।

तार पर कपड़े फैलाते समय लगा करंट, मां-बेटी की मौत



बाराबंकी (संवाददाता)। कस्बा असंद्रा में बुधवार दोपहर लोहे के तार पर सूखने के लिए कपड़े डालते समय मां-बेटी करंट की चपेट में आ गईं। इस हादसे में दोनों की ही मौत हो गई। कपड़े फैलाते समय पहले युवती फिर उसकी मां करंट की चपेट में आईं। करंट से झुलसी मां-बेटी को परिजन इलाज के लिए एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे से परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। युवती एक निजी

स्कूल में शिक्षिका थीं।असंद्रा थाने से चंद कदमों की दूरी पर असंद्रा कस्बे के पड़ोसैयद मोहल्ला निवासी अली हैदर की पत्नी कनीज फातिमा (45) बुधवार को पुत्री चमन जहरा (22) के साथ घर में कपड़े धो रही थीं। कपड़ों को सूखने के लिए चमन जहरा घर के सामने रखे टिनशेड में लगे लोहे के पाइप से बंधे लोहे के तार पर फैलाने लगीं। जैसे ही उसका हाथ तार से छूआ वह तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आ गईं। उसको तड़पता देख बहवास में कनीज फातिमा उसे बचाने दौड़ी तो वह भी करंट की चपेट में आ गईं। मां-बेटी को करंट से छिपकता देख मौजूद पड़ोसी युवक मोहम्मद ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने सूखे डंडे के सहारे तार से छिपकी मां-बेटी को छुड़ाया।

बकरी चराने गए बुजुर्ग का शव चार दिन बाद नहर में मिला

बेटे ने पिता की मौत की जांच की मांग की मुन्नालाल ने बताया कि उनके पिता काफी बुजुर्ग थे

सीतापुर (संवाददाता)। क्षेत्र के सहादतनगर निवासी बुजुर्ग चार दिन पहले बकरी चराने घर से निकले थे। देर शाम तक जब वापस नहीं आए तो परिजनों ने तलाश की। नहर के किनारे उनका चरमा, अंगोछा व डंडा मिला था। पारा गांव के पास नहर में उनका शव उतराता मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सहादतनगर निवासी मिश्री लाल (70) गांव के पश्चिम नहर के किनारे बकरी चराने गए थे। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। नहर के किनारे उनका चरमा, अंगोछा व डंडा पड़ा मिला था। परिजनों को आशंका हुई कि वह कहीं चले गए हैं। इसके बाद थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस को सूचना दी।आसपास के गन्ने के खेतों में ड्रोन कैमरे से उनकी तलाश की गई। साथ ही नहर का पानी बंद करवाकर पुलिस ने तलाश करवाई। बुधवार सुबह सहादतनगर से करीब छह किमी दूर पारा गांव के निकट मिश्री लाल का शव नहर में उतराता



निकट नहर में शव उतराता हुआ मिला।बेटे ने पिता की मौत की जांच की मांग की मुन्नालाल ने बताया कि उनके पिता काफी बुजुर्ग थे। वह नहर में कैसे गिर गए, इसकी जांच होनी चाहिए। पिता को ड्रोन कैमरे की मदद से भी तलाश गया था। चार दिन से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। नहर के किनारे उनका चरमा, अंगोछा व डंडा मिला था। पारा गांव के पास नहर में

उनका शव उतराता मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सहादतनगर निवासी मिश्री लाल (70) गांव के पश्चिम नहर के किनारे बकरी चराने गए थे। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। नहर के किनारे उनका चरमा, अंगोछा व डंडा पड़ा मिला था। परिजनों की आशंका हुई कि वह कहीं चले गए

दी।आसपास के गन्ने के खेतों में ड्रोन कैमरे से उनकी तलाश की गई। साथ ही नहर का पानी बंद करवाकर पुलिस ने तलाश करवाई। बुधवार सुबह सहादतनगर से करीब छह किमी दूर पारा गांव के निकट मिश्री लाल का शव नहर में उतराता हुआ दिखा। शव मिलने की सूचना पाकर सहादतनगर निवासी मुन्ना लाल भी मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष इमलिया सुल्तानपुर श्यामू कर्नौजिया ने बताया कि मिश्री लाल बकरी चराने गए थे।

कोरौंध और गोनी की माटी में खेले शुभांशु अब अंतरिक्ष की सैर पर

हरदोई (संवाददाता)। अनगिनत लोगों के शुभकामनाओं के साथ थ्रूप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर दी है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके पैतृक गांव और ननिहाल में खुशी का माहौल है। शुभांशु मूलरूप से भरावन विकास खंड के कोरौंध गांव के रहने वाले हैं। उनका ननिहाल भी इसी विकास खंड के गोनी गाँवसा गांव में है। उनके शुभ चिंतकों, दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनकी उपलब्धि पर गांव में मिठाई और फल बाँटकर खुशी जताई। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनने का गौरव हासिल करने वाले शुभांशु शुक्ला यूँ तो पिछले कई साल से गांव नहीं आए, लेकिन बचपन में यहां खूब आते थे। यहीं के मैदान और मिट्टी में खेलते थे। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला लखनऊ संविद्यालय में सेवारत थे। के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मां आशा शुक्ला गृहिणी हैं। शुभांशु के पैतृक गांव में विवेक सिंह, अमित सिंह, रामचंद्र शर्मा, राजाराम गौतम आदि ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और खुशी जताई।

महिला अस्पताल से नवजात चोरी, पीड़ित पिता बोला- झपकी लगी..जागे तो गायब था, जांच में जुटी पुलिस



हरदोई (संवाददाता)। हरदोई जिले में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महिला चिकित्सालय से नवजात चोरी हो गया। बृहस्पतिवार सुबह लगभग तीन बजे घटना का पता चलने पर सनसनी फैल गई। हरियाणा थाना क्षेत्र के बिलाहरि गांव निवासी शिवानंद दीक्षित ने बीती 19 जून को प्रसव पीड़ा होने पर अपनी पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। ऑपरेशन के बाद उन्होंने बेटे को जन्म दिया था। शिवानंद के मुताबिक रात दो बजे तक वह जागता रहा। इसके बाद झपकी लग गई। लगभग तीन बजे जब वह जागा, तो बच्चा मौजूद नहीं था। इसके बाद उसने काफी तलाश भी किया, लेकिन कोई सुराग नहीं

मिला। उसने यूपी 112 पर सूचना दी। जानकारी पर सीओ सिटी अंकित मिश्रा, शहर कोतवाल संजय त्यागी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटना की जांच की जा रही है। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार मुंशी की मौत बेहंदर। संडीला-मल्लावां मार्ग पर कहली गांव के पास पिकअप ने बाइक सवार मुंशी को टक्कर मार दी। बुधवार दोपहर हुई घटना में मुंशी की मौत हो गई। कासिमपुर थाना क्षेत्र के कहली गांव निवासी रामगोपाल (50) संडीला तहसील में एक अधिवक्ता के पास मुंशी थे। रोज की तरह वह बुधवार सुबह बाइक से तहती कराया था। ऑपरेशन के बाद उन्होंने बेटे को जन्म दिया था। शिवानंद के मुताबिक रात दो बजे तक वह जागता रहा। इसके बाद झपकी लग गई। लगभग तीन बजे जब वह जागा, तो बच्चा मौजूद नहीं था। इसके बाद उसने काफी तलाश भी किया, लेकिन कोई सुराग नहीं

नशे की लत को भुना रहा ऑनलाइन बाजार... युवा खरीद रहे ड्रग्स, हो रहे बीमार



गोरखपुर (संवाददाता)। सोशल मीडिया के खतरे हजार हैं। इस प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे वेबसाइट उपलब्ध हैं, जहां से युवाओं को आसानी से ड्रग्स मिला जा रहे हैं। यही नहीं, इलाज के लिए मिलने वाली दवाओं का नशे के लिए इ इडल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी लत युवाओं को बीमार बना रही है। दो-चार रुपये में मिलने वाली इन दवाओं को मानक से ज्यादा इस्तेमाल कर युवा पीढ़ी नशे की आगोश में डूब जा रही है। अब जब दवा की दुकानों पर सख्ती बढ़ी है तो ऑनलाइन बाजार से सिंथेटिक दवाओं की खरीदारी कर युवा अपनी लत पूरा करने में लगे हैं। इससे जहां उन्हें संक्रमण और बीमारी घेर रही है, वहीं विभाग भी तमाम कोशिशों के बाद भी इस पर

लगेम लगाने में नाकाम है। नारकोटिक्स विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इन दिनों कुछ युवाओं ने नशे के ट्रेंड को बदल दिया है। पुराने परंपरागत नशे के मादक पदार्थों के दाम बढ़ने और इनकी सीधी निगरानी होने से लती युवा अब ऑनलाइन वेबसाइट और एप के जरिये सिंथेटिक ड्रग्स की बुकिंग करवा रहे हैं। इससे नशीला पदार्थ (सिंथेटिक ड्रग्स) इन तक आसानी से पहुंच जा रहा है। जो दवा बीमारी से निजात दिलाने के लिए बनाई गई है, उसका उपयोग अब युवाओं अपने नशे के लिए कर रहे हैं। इसके लिए अब पान, बीड़ी, सिगरेट और शराब के अलावा कम खर्च में नशीली दवा सिराप और इंजेक्शन का उपयोग अधिक हो रहा है। दर्द और एलर्जी से राहत दिलाने के लिए बनाई गई दवाओं का इस्तेमाल युवा नशे से लिए करने लगे हैं। दवा के एक व्यापारी ने बताया कि पेटेंटिन इंजेक्शन, कोरेक्स सीरप और स्पामो प्रॉक्सीवान कैप्सूल का उपयोग नशे के लिए किया जा रहा है।

बाग में मिला युवती का शव, प्रेमी पर हत्या का आरोप

बाराबंकी (संवाददाता)। रामनगर कोतवाली क्षेत्र के तालपाल पुरवा गांव में सुबह बाग में युवती का शव संदिग्ध दशा में मिला। शव नीम के पेड़ के सहारे ऐसे टिका था जैसे युवती बैठी हो। उसके मुंह से खून निकल रहा था, साथ ही गले में चोट के निशान भी मिले हैं। परिजनों ने युवती के प्रेमी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने के साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।तालपाल पुरवा निवासी मुन्नालाल के मुताबिक उनकी तीन बहनें हैं। माता-पिता का निधन हो चुका है। दूसरे नंबर की बहन नीरज कुमारी (30) का बीते आठ साल से गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गांव में मकान के अलावा बाहर की ओर अहाता है। मंगलवार की रात करीब आठ बजे खाना खाने के बाद नीरज कुमारी परिजनों के साथ सोने चली गई थी।

रीवां माइनर कटने से खेतों में भरा पानी

बाराबंकी (संवाददाता)। तहसील क्षेत्र के बिसाही मजरे जाफरपुर गांव के पास मंगलवार की देर रात रीवां माइनर कटने से खेतों में पानी भर गया। पानी भरने से कई किसानों की धान की बेरन जलमग्न हो गई। किसान हसरराज, अंकित व पुष्पेन्द्र आदि ने बताया कि फसल में पानी ज्यादा भर जाने से बेरन के नष्ट होने का अंदेशा सताने लगा है। सिंचाई विभाग को नहर की पटरी कटने की सूचना दिए जाने के 10 घंटे बाद बुधवार को कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मगर तेज बहाव के कारण कटी हुई माइनर की मरमत्त नहीं हो सकी। ऐसे में किसानों की मदद से किसी तरह कटान को बंद कराया गया। किसान हसरराज ने बताया कि बेरन नष्ट होने से अब दोबारा करनी पड़ेगी। इससे धान की फसल अब करीब 15 दिन बिंबल से रोपी जाएगी।

आज भी ढिबरी के सहारे एक गांव

बाराबंकी (संवाददाता)। यह सुनकर अचंभा होगा कि रमार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया के इस दौर में जिले का एक गांव अभी भी ढिबरी व मोमबत्ती की रोशनी के सहारे है। आजादी के 77 साल बाद भी जिले के जहांगीराबाद क्षेत्र के गडरियनपुरवा गांव में अभी तक बिजली के बल्ब की रोशनी नहीं पहुंची है। बचपन से गांव में बिजली आने का इंतजार कर रहे लोगों का सपना बुढ़ापे तक अधूरा बना है। जहांगीराबाद क्षेत्र का यह गांव शाम होते ही अधरे में डूब जाता है। यहां के बच्चे ढिबरी युग में पढ़-बढ़ रहे हैं। बिजली के बल्ब की रोशनी का इंतजार कर रहे यहां के बुजुर्गों को उम्मीद है कि शायद उनके बच्चों को बिजली की सुविधा मयस्सर हो सकेगी।

हाईवे पर दोपहिया वाहनों का बाजार, चलना दुश्वार

बाराबंकी (संवाददाता)। शहर से होकर गुजरे लखनऊ-अयोध्या हाईवे की पटरी पर दोपहिया वाहनों का बाजार चलने से वाहन तो छोड़िए लोगों का पैदल चलना तक दुश्वार है। सड़क पर ही वाहनों की होने वाली बेतरतीब पार्किंग के कारण आए दिन वाहन चालकों को घंटों जाम की परेशानी से जूझना पड़ता है। शिकायत के बाद भी हाईवे पटरी को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर जिम्मेदार उदासीन बने हैं। इससे बेखोफ तरह से पटरी पर दोपहिया व चार पहिया वाहनों की मरम्मत के साथ अस्थायी दुकानें संचालित हो रही हैं। नगर पालिका परिषद के ईओ संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि सड़क पर दोपहिया व चार पहिया वाहन खड़े करने के साथ पटरी पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

बुजुर्ग पर दबंगों ने किया चाकुओं से हमला

सीतापुर (संवाददाता)। महोली की उरदौली बाजार में मंगलवार रात विवाद के बाद दबंगों ने बुजुर्ग पर चाकु से हमला कर दिया। जलालपुर निवासी रामलोटन (60) के अनुसार मंगलवार शाम वह कुसेला गांव के निकट खेतों में अपने मेमोरी चरा रहे थे। उसी दौरान नेकपुर निवासी सीतामन, उनके पुत्र अन्नूप ने वहां आकर बेवजह विवाद शुरू कर दिया। राहगीरों के समझाने पर वे लोग ध्मकी देकर चले गए। रामलोटन ने बताया कि देर शाम उरदौली बाजार में सब्जी खरीदने के दौरान वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने उनको लोहे की रॉड से पीटते हुए चाकु से हमला कर दिया। इससे बेसुध होकर वह जमीन पर गिर पड़े। घटना से बाजार में अफरातफरी मच गई।

नहीं मिला है। बीते शनिवार की रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरासत गलियारा के निरीक्षण के दौरान प्रभावित सभी लोगों को मुआवजा देने के निर्देश दिए थे। उससे पहले अधिकांश जमीन किसी न किसी रियासत या जमींदार की थी। एकट लागू होने के बाद जहां खेत था, उसका किसानों में बंटवारा हो गया। चकबंदी के दौरान उस पर किसानों का नाम दर्ज कर दिया गया, लेकिन जहां घर बन गए थे,

कार्यकर्ताओं में आधे घंटे तक धक्का-मुक्की होती रही। इस दौरान एक सपा नेता की गाड़ी का शीशा भी टूट गया और उस पर लगा पार्टी का झंडा किसी ने निकाल दिया। बाद में पुलिस अफसरों ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। नेता प्रतिष्ठा माता प्रसाद पांडेय ने इसे विधेयाधिकार हनन का मामला बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले को वह विधानसभा में उठाएंगे। वहीं यक्ष अखिलेश को पूरे प्रकरण की जानकारी देने और उनके निर्देश पर अगला कदम उठाने की बात कही। रिकर्डों में नाम दर्ज न होने की वजह से विरासत गलियारा के लिए चौड़ीकरण से प्रभावित करीब 300 लोगों को जमीन का मुआवजा



नहीं मिला है। बीते शनिवार की रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरासत गलियारा के निरीक्षण के दौरान प्रभावित सभी लोगों को मुआवजा देने के निर्देश दिए थे। उससे पहले अधिकांश जमीन किसी न किसी रियासत या जमींदार की थी। एकट लागू होने के बाद जहां खेत था, उसका किसानों में बंटवारा हो गया। चकबंदी के दौरान उस पर किसानों का नाम दर्ज कर दिया गया, लेकिन जहां घर बन गए थे,

आपातकाल का इतिहास एक काला अध्याय हो गया है। केन्द्रीय मंत्री राकेश सचान।



उत्तरौला बलरामपुरछ्ठ बुधवार को मनकापुर रोड पर स्थित रायल मैरेज हाल में आपात काल के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबि नेट मंत्री राकेश सचान व विशिष्ट अतिथि अव ध क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री कैप्टन विकास सिंह भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने संगोष्ठी के दौरान अपने मां के नाम एक नीम का पौधा वृक्षा रोप ण करने के बाद मंत्री जी ने कहा कि 25जून 1975 का दिन भारत ध्के लोकतन्त्र का सबसे शर्मनाक और काला दिन था।पुरे देश में लगाई गई एमरजेंसी को देश कभी नहीं भूलेंगा।जो लोग

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आगामी त्याहारों के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न



श्रावस्ती, 26 जून, 2025। सु०वि०। आगामी त्योहारों में श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, मोहरम एवं कजरी तीज को दृ ष्टिगत रखते हुए शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की अध्यक्षता में सम्बन्धित नोडल अधिकारियों एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन सभी त्योहारों को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। त्योहारों के दौरान कोई भी नई परम्परा कायम करने की कोशिश नही की जायेगी। जिससे अमन–चौन में बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो। यदि कोई भी व्यक्ति अमन–चौन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते पाया जाए, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिाकारी जुलूस के दौरान भ्रमणशील रहेंगे। कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं रहेगा। मोहरम त्योहार के दृष्टिगत जुलूस के दौरान

हाटन रोडध्वचपेड़वा मार्ग पर जाम लगने की स्थिति।



नगर की घनी आबादी के बीच गुजरने वाली सड़क हाटन रोडध्वच पेड़वा मार्ग पर बड़े वाहनों के आवागमन की कोई समय सारणी तय नहीं की गई है और न तो नगर के बाशिंदों को जाम की समस्या से निजात मिल पाया भी बड़ी मुश्किल हो गया है। यही हालध श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे की है, कि दिन में कई बार जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। हालांकि नगर पालिा का प्रशासन ने इस पर गम्भीर समस्या कोलेकर प्रशानिक अधिकारियों के साथ बैठक कर इस गम्भीर समस्या का हल करने का प्रयास किया। परन्तु किन्हीं कारण वश उनकी यह प्रयास सफल नहीं हो सका है। और नगर वासियों को राजकीय बालिका इन्टर कॉलेज व हाटन रोड पर नगर वासियों नेउत्तरौला पचपेड़वा मार्ग परआवा गमन सुलभ करने की मांग की है।

संविधान हाथ में लेकर देश में घूम रहे हैं, उनकी ही पार्टी की प्र ध ानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान का गला घोटने का कार्य किया था। इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने पद धारण को आयो्ग्य ठहरा दिया था। अपनी सत्ता और पद को बचाने के लिए लाखों लोगों को बिना कारण जेल में बन्द कर दिया गया था। उस समय मीडिया समाचार पत्र टेलीविजन और रेडियो सहित तमाम संचार के माध्यम पर प्रतिबंध ा लगाने का कार्य किया गया। सरकार के खिलाफ उठी हर आवाज को दबाने का कार्य किया गया है।आज पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर उस कांग्रेस द्वारा किए अत्याचार को बताने का कार्य करना चाहिए। और कांग्रेस से सवाल भी करना चाहिए। गोष्ठी में लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा, उत्तरौला

विधायक राम प्रताप वर्मा,सदर विधायक पल्दू राम, तुलसीपुर के विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आरती तिवारी, प्रदीप सिंह, चन्द्र प्रकाश सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष डाक्टर धीरेन्द्र प्रताप उर्फ धीरू सिंह,उत्तरौला ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि ा महि पाल चौधरी, उत्तरौला नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अनूप चन्द गुप्ता,गैडास बुजुर्ग ब्लाक प्रमुख राकेश तिवारी,संदीप कुमार वर्मा,फणींद्र गुप्ता,ओम प्रकाश गुप्ता, सहित भाजपा के सैकड़ों पदाधिाकारी व कार्य कर्ता मौजूद रहे।इसी दौरान उत्तरौला में आयोजित आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर केन्द्रीय मंत्री ने लोक तन्त्र रक्षक सेनानी चौध री इरशाद अहमद गद्दी, शिवप्रसादद्विवेदी, ओमप्रकाश त्रिपाठी, अयोध्या प्रसाद को अंग वस्त्र औरस्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मा नित किया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने सालिक राम जय सलू ल.किशोरी लाल मोदन वाल, बरसाती शर्मा, नवल किशोर,मंगल प्रसाद,जुग्गी लाल, दलजीत सिंह, प्यारे लाल, मनीराम, रामा नन्द व जगराम को भी सम्मानित किया गया।

सभी अधिकारीगण जुलूस के दौरान रहेंगे भ्रमणशील—जिलाधिकारी आगामी त्योहारों को देखते हुए बिजली, पानी एवं साफ—सफाई की मुकम्मल व्यवस्था करें सम्बन्धित अधिकारीगण—जिलाधिकारी

अपने–अपने क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेंगें थानाध्यक्षगण—पुलिस अधीक्षक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, और बार–बार हो रही बिजली कटौती रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जाए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में साफ–सफाई व पेयजल हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी वहीं नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में साफ–सफाई एवं पेयजल हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने मोहरम को शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी उप जिलाधिकारियों, सम्बन्धित अधिाकारियोंधुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि मोहरम त्योहार व आगामी पड़ने वाले त्योहारों को शासन की गाइडलाइन के अनुसार शान्तिपूर्णध्सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाये जाने के लिए अपने स्तर से समस्त तैयारियां पूर्ण करा लें, ताकि कोई भी समस्या किसी भी दशा में उत्पन्न न होने पाये। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने–अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के साथ ही त्योहार वाले दिन कड़ी सुरक्षा व निगरानी रखेंगे।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि